

- केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बताया है।
- वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी परिषद ने दो प्रमुख मंत्रिसमूहों का गठन करने का निर्णय लिया है।
- मध्योत्तर अंडमान जिला प्रशासन को आई एस ओ नौ हजार एक से सम्मानित किया गया है।
- सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुधार की दिशा में परिवहन विभाग की ओर से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- विश्व पर्यटन दिवस के सिलसिले में कला और संस्कृति विभाग नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा चित्रकारी व चित्रकला प्रतियोगिता व प्रदर्शनी का आयोजन करेगा।

<><><><><><>

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बताया है। श्री शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी) के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। श्री शाह ने कहा कि देश की प्रगति साइबर सुरक्षा के बगैर संभव नहीं है। श्री शाह ने सभी हितधारकों से इस खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि डिजिटल लेनदेन और डिजिटल आंकड़ों का इस्तेमाल देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस कारण साइबर सुरक्षा से जुड़े लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। श्री शाह ने कहा कि हाल ही में प्रभावी तीन आपराधिक कानूनों में देश में साइबर अपराध से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। संदिग्ध पंजीकरण की आई4सी पहल को लेकर श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर का साइबर संदिग्ध पंजीकरण भविष्य में अपराधों को रोकने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि आई4सी साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने जा रहा है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया।

<><><><><><>

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में संपन्न जीएसटी परिषद की चौवनवीं बैठक के बाद कहा कि जीएसटी परिषद ने दो प्रमुख मंत्रिसमूहों का गठन करने का निर्णय लिया है। इनमें से एक समूह चिकित्सा और जीवन बीमा संबंधी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर काम करेगा और दूसरा मुआवजा उपकर के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक नवंबर में होगी, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा संबंधी नए मंत्रिसमूह की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। सुश्री सीतारामन ने कहा कि यह मंत्रिसमूह अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट देगा। मंत्रिसमूह वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित बीमा मामलों, जीवन बीमा, सावधि जीवन बीमा, समूह बीमा आदि पर भी विचार करेगा।

<><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान जिला प्रशासन को आई एस ओ नौ हजार एक से सम्मानित किया गया है। जिला प्रशासन के साथ इसके अधीन राजस्व कार्यालय को भी ये प्रमाणन प्रदान किया गया है। प्रमाणन समारोह का आज मुख्य सचिव केशव चन्द्र ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने सुशासन और सेवाएं प्रदान करने में जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हुए कहा कि आई एस ओ नौ हजार एक प्रमाणन सिर्फ एक मान्यता नहीं है, बल्कि गुणवत्ता को बनाए रखते हुए सेवाओं में निरंतर सुधार के लिए जिम्मेदारी भी है। ये उपलब्धि जिला प्रशासन की सुशासन के सिद्धान्तों को अमल में लाने के लिए उनके समर्पित प्रयासों और पारदर्शिता का परिणाम है। जिला उपायुक्त दिलखुश मीणा ने मुख्य सचिव सहित आयुक्त को भी निरंतर जिला प्रशासन को सहयोग देने के लिए अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन गुणवत्ता सेवाएं और असरदार सुशासन को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इससे आम जनता को लाभ मिल सके। समारोह में रंगत के सहायक आयुक्त और डिगलीपुर तहसील के प्रतिनिधि भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

<><><><><><>

